पूर्वोत्तर परिषद को प्रधानमंत्री जी का संबोधन

दिनांक 12 अप्रैल, 2005
नई दिल्ली

मुझे इस पुनर्गठित पूर्वोत्तर परिषद जो अब पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक सांविधिक आयोजना निकाय है, के प्रथम सत्र में उपस्थित होकर अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है। मेरी इच्छा थी कि इसके लिए मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र में जाता लेकिन समय की कमी आड़े आ गई। इस अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र के सामाजिक तथा आर्थिक विकास के भविष्य की दिशा तय करने हेतु की गई यह पहल इस निकाय के हाथों में है। मेरी कामना है कि यह अपने प्रयासों में सफल हो।

पूर्वोत्तर क्षेत्र मेरा दूसरा घर है। पिछले दो दशकों से राज्य सभा में इस क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में मैं इसका दत्तक पुत्र बन गया हूं। यहां के लोगों ने मेरे प्रति असीम प्यार, सम्मान तथा लगाव दर्शाया है, जिससे मैं वास्तव में, अभिभूत हूँ। मैं इसका मूल्य अपने इस जीवन में नहीं चुका सकता। यह मेरी श्रद्धा का एक छोटा सा प्रतीक है कि मैंने पूर्वोत्तर परिषद को पुनर्जीवित करने में व्यक्तिगत रुचि दिखलाई है ताकि हम इस क्षेत्र का समेकित तथा ठोस विकास सुनिश्चित कर सकें।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में इसकी अनूकूल प्राकृतिक तथा भौगोलिक परिस्थितियों के कारण विकास की काफी संभावनाएं हैं। ग्रामीण परिवारों की आय के स्तर को कृषि, बागवानी, चिकित्सा तथा प्राकृतिक जड़ी-बूटियों और बांस, जल तथा पवन ऊर्जा और खनिज पदार्थ जैसे कुछ क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध विशाल संभावनाओं का उपयोग करके व्यावहारिक तौर पर काफी अधिक बढ़ाया जा सकता है। इस क्षेत्र के राज्यों के आर्थिक तथा भौगोलिक आकार को देखते हुए विकास के लिए एक क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाने का काफी महत्व है। मुझे पूरी आशा है कि पूर्वोत्तर एक समग्र क्षेत्र के रूप में सामने आएगा जो इस पूरे क्षेत्र के आर्थिक व सामाजिक विकास तथा समृद्धि के लिए समर्पित होगा।

पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना विकास के लिए समेकित, समग्र तथा क्षेत्रीय दृष्टिकोण उपलब्ध कराने हेतु की गई थी। इसका अभिप्राय बृहत्तर क्षेत्रीय प्रासंगिकता वाले मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना था। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए लघु योजना आयोग के रूप में, इसका उद्देश्य उन बहिर्मुखताओं पर अधिकार रखना था जो विकास, विशेषकर भौतिक तथा मानव आधारभूत ढांचे के विकास तक क्षेत्रीय पहुंच रखती हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए तैयार किए गए विकास कार्यक्रमों से यह आशा की गई थी कि वे आवश्यक क्षेत्रीय दृष्टिकोण प्रदान करें। इसकी परिकल्पना एक ऐसे निकाय के रूप में भी की गई थी जो राज्य सरकारों को परियोजना डिजाइन उपलब्ध कराने, उन्हें तैयार करने तथा उनके कार्यान्वयन में सहायता देने हेतु अपेक्षित क्षमता विकसित कर सके ताकि वे बृहत परियोजनाओं को सही ढंग से कार्यान्वित कर सकें। इसके अतिरिक्त, पूर्वोत्तर परिषद को विकास तथा सुरक्षा के बीच परस्पर सम्बंध को देखते हुए इन दोनों पर विशेष ध्यान केंद्रित करना था।

हालांकि, मैं समझता हूं कि हमें यह समझना चाहिए कि पूर्वोत्तर परिषद इन अपेक्षाओं पर पूरी तरह से खरी नहीं उतरी है, बल्कि यह एक निधियां बांटने वाली निकाय बन गई है। यह राज्यों में, जो भी संसाधन इसके पास उपलब्ध होते हैं, उनका यांत्रिक ढंग से आबंटन कर रही है। मुझे खेद है कि इस निकाय को पुनर्जीवित करने के लिए अभी भी काफी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है और तभी यह अपने वास्तविक उद्देश्य तथा अब पुनः लागू किए जाने वाले अपने दायित्व को पूरा करने में सक्षम हो सकेगी। विगत में इसके कार्य-कलापों में सुरक्षा पहलुओं की लगभग पूरी तरह से अनदेखी की गई है और हम भविष्य में ऐसा होते रहना सहन नहीं कर सकते।

पूर्वोत्तर परिषद को इस ढंग से पुनर्गठित किया गया है कि जिससे यह अपने कंधों पर आई भारी जिम्मेवारी का निर्वहन आसानी से कर सके। पूर्वोत्तर परिषद के गठन को देखते हुए अब किसी के पास शिकायत का कोई मौका नहीं रह जाएगा जो कार्य करने, अनुमोदन प्राप्त करने अथवा निर्णय लेने की प्रक्रिया में होने वाली देरी के कारण हुआ करता है। योजना आयोग के संबंधित सदस्य के पूर्वोत्तर परिषद के नामित सदस्यों में से एक सदस्य होने के कारण अब क्षेत्रीय योजना निकाय तथा राष्ट्रीय योजना आयोग के बीच संपूर्ण तालमेल होना चाहिए। दो अन्य पूर्णकालिक नामित सदस्य अपने लम्बे अनुभव, सुविज्ञता, इस क्षेत्र के साथ काफी अरसे से जुड़ाव तथा क्षेत्र की समस्याओं की समझ होने के कारण निःसंदेह न केवल नीति-निर्धारण में अत्यधिक योगदान देंगे बल्कि केंद्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के साथ ठोस समन्वय स्थापित करके प्रभावी ढंग से तथा शीघ्रता और मितव्ययता के साथ कार्यान्वयन सुनिश्चित कर सकेंगे।

इसके लिए पहली जरूरत यह है कि सभी के समझने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में एक समग्र रूपरेखा तैयार करनी होगी। मुझे खुशी है कि अध्यक्ष 15 वर्षों के उद्देश्य को ध्यान में रखकर पूर्वोत्तर क्षेत्र- 2020 नामक एक "विजन डाक्यूमेंट" तैयार करने के लिए एक कार्य-योजना बना रहे हैं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि यह "विजन डाक्यूमेंट" जनता के विभिन्न वर्गों की सहभागिता से तैयार किया जाएगा। इसे जनता की योजना के रूप में महसूस किया जाना चाहिए। इसका दृष्टिकोण पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्व-शासन की सुदृढ़ परंपराओं के अनुरूप भी होगा। योजना बनाने की विभिन्न मदों के लिए युवाओं की कुशाग्र सहभागिता, विशेषकर विश्वविद्यालयी छात्रों और संकाय का सहयोग उनके लिए भविष्य में उन्नति की एक किरण दिखाएगा। उन्हें इस "विजन " में विश्वास व्यक्त करना चाहिए और उनके लिए उपलब्ध कराए जा रहे रचनात्मक अवसरों पर गौर करना चाहिए।

विकास तथा सुरक्षा पहलू साथ-साथ चलने चाहिए। इस क्षेत्र की सामूहिक समझदारी को देखते हुए पूर्वोत्तर परिषद सुरक्षा संबंधी जरूरतों के साथ विकास के लक्ष्यों तथा प्रयासों को इकट्ठा करने की अच्छी स्थिति में है। गृह मंत्रालय की सहमति से पुनर्गठन रिपोर्ट में दिए गए सुझाव का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाना चाहिए।

पूर्वोत्तर परिषद में आंतरिक आयोजना की सुविज्ञता की कमी एक समस्या हो सकती है। इसका उत्तर इस प्रयोजन के लिए प्रतिभाओं को काम में लगाने हेतु लोगों की भागीदारी प्राप्त करने में मिल सकता है। सभी आवश्यक प्रतिभा तथा सुविज्ञता इसी क्षेत्र में अब बड़ी संख्या में उपलब्ध है जो पूर्वोत्तर परिषद द्वारा काम में लाए जाने के लिए तैयार है। उनके द्वारा प्रस्तुत किए

गए तरीके वास्तव में लोगों को और भी अधिक स्वीकार्य हो सकते हैं। इसके साथ ही, समवर्ती मॉनिटरिंग तथा मूल्यांकन में लगाए गए विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, सामाजिक ग्रुपों, पंचायतों, शहरी निकायों और सामुदायिक संगठनों की भागीदारी से उत्तरदायित्व की भावना में काफी सुधार लाया जा सकता है। हम अधिकांश विकास परियोजनाओं में खामियों की समस्या की शिकायत करते हैं। कुछ मायनों में यह समस्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में अधिक गंभीर है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन खामियों पर नियंत्रण पाना तथा उन पर रोक लगाना देश के शेष भागों में, विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में शासन की प्रक्रिया की एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय होना चाहिए।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में उपलब्ध मानव संसाधन का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर विकास करने की आवश्यकता है। कार्यबल की कुशलता को बढ़ाने का कार्य, जोकि इस क्षेत्र के लिए प्रासंगिक है, गंभीरता से किया जाना चाहिए। इस सम्मेलन में मेरे लिए यह बताना उचित होगा कि अनेक पूर्वोत्तर राज्यों में विज्ञान तथा गणित की पढ़ाई एक अत्यन्त कमजोर बिंदु रहा है और इसका परिणाम यह होता है कि हम ऐसे स्नातक तैयार कर रहे हैं जिनके पास रोजगार योग्य कुशलता नहीं होती। इसलिए पूर्वोत्तर क्षेत्र का शिक्षा ढांचा फिर से तैयार करना इस परिषद का प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए। कमजोर शिक्षा आधार की समस्या विशेष रूप से जिला स्वायत्त परिषद द्वारा शासित क्षेत्रों में ज्यादा गंभीर है। मैं नहीं जानता हूँ कि यह इस परिषद के कार्यक्षेत्र में आता है, बल्कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के नौजवानों को लाभप्रद रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए शिक्षा की एक समग्र आयोजना तथा रोजगारपरक कौशल अनिवार्य है। सबसे निचले स्तर पर विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संबंधी निवेशों की जरूरत होगी ताकि गुणवत्ता में सुधार किया जा सके, लागत में कमी लाई जा सके तथा उत्पादों की किस्में बढ़ायी जा सकें। इसके साथ-साथ, विपणन श्रृंखला भी विकसित करनी होगी। प्राथमिक स्थानीय स्तर पर मूल्यवर्धन से पारिवारिक स्तर पर आय में वृद्धि होगी और वित्तीय सुरक्षा तथा मनोवैज्ञानिक संतुष्टि का भाव मिलेगा। इससे उनमें अपने उद्यमों का विकास करने के लिए बैंकों से ऋण लेने तथा प्राप्त लाभ से समय पर ऋण की वापसी-अदायगी करने का विश्वास भी बढ़ेगा। इससे उद्यम की निरन्तरता भी बनी रहेगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र में ऋण-जमा का अनुपात पिछले अनेक वर्षों में विशेष तौर पर कम रहा है। इसे बदलना होगा। इसका अर्थ यह है कि इस क्षेत्र के लिए विकास आयोजनाओं में पर्याप्त व्यवहार्य परियोजनाएं होनी चाहिए। इस श्रृंखला को पूरा करने के लिए विपणन के अवसरों को विकसित करना होगा विशेषकर जब हम संसाधन आधारित उद्योगों, कृषि प्रसंस्करण तथा इन सब बातों की चर्चा कर रहे हों।

मेरा सुझाव है कि पूर्वोत्तर परिषद बाजार केंद्रों से आसानी से संपर्क बनाने, विपणन कौशल प्रदान करने, प्रक्रियाओं को सरल बनाने और उन स्थानीय समस्याओं जो कमजोर उद्यमियों को निरूत्साहित करती हैं, को कम करने के साथ-साथ विकास केंद्रों को स्वरूप प्रदान करे तथा उनकी योजना बनाए।

भारत सरकार की पूर्वोन्मुख नीति का पूरा लाभ उठाया जाए। आसियान बाजार पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए बागवानी, पुष्प कृषि तथा औषधीय जड़ी-बूटियों को बढ़ावा देने के लिए बड़े अवसर उपलब्ध करा रहा है। यदि एक बार भूमि संपर्क के मामले में सुधार कर लिया जाए तो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से लगाव हमारे उत्पादों को स्वीकार्य तथा बिक्री योग्य बना देगा। आवश्यकता पड़ने पर वायु संपर्क पर भी विचार किया जा सकता है। इस संबंध में संभावित क्षेत्र हैं– सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन, खान तथा खनिज पदार्थ, गैस, तेल, अनुप्रवाह वाले उद्योग,

शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएं आदि। पूर्वोत्तर परिषद क्षेत्रीय स्तर पर एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने के लिए संबंधित मंत्रालयों के साथ संपर्क करके सरकारी नीतियों के कार्यान्वयन को मूर्त रूप देने के लिए सर्वोत्तम स्थिति में है।

मुझे विश्वास है कि पूर्वोत्तर परिषद, क्षेत्र के आयोजना निकाय के रूप में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को लाभप्रद तथा रचनात्मक कार्यों में लगाने में सक्षम होगा तथा उनमें कानून तथा व्यवस्था और लोगों के बीच शांति बनाए रखने के प्रति रूचि पैदा करेगा ताकि वे सम्पन्नता की ओर अग्रसर हो सकें और इस प्रकार, इस क्षेत्र को प्रगति, शांति तथा समृद्धि के मार्ग पर ले जाया जा सके।

पूर्वोत्तर क्षेत्र आज विकास, शांति तथा सम्पन्नता की एक नई लहर के शीर्ष पर खड़ा है। मैं इस क्षेत्र के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार हमेशा उनके साथ है और उनके कल्याण तथा प्रग्रति के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध रहेगी। मेरी कामना है कि पूर्वोत्तर परिषद को अपने विचार-विमर्शों में पूर्ण सफलता मिले।

....